भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3712

उत्तर देने की तारीख-25/03/2026

इंजीनियरिंग शिक्षा में सुधार और स्नातकों की रोजगार क्षमता में सुधार

3712 **डा. अजित माधवराव गोपछड़े:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंजीनियरिंग स्नातकों की बढ़ती वार्षिक संख्या और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में सीमित मांग के बीच बढ़ते असंतुलन की समीक्षा की है, जिसके परिणामस्वरूप कुशल युवाओं की रोजगार-योग्यता तथा उनके उपयोग में कमी आ रही है;

(ख) क्या एआईसीटीई और उद्योग निकायों द्वारा निम्न गुणवत्ता, पुराने पाठ्यक्रम, संकाय की कमी और निम्न स्तर वाले इंजीनियरिंग संस्थानों के बंद होने से संबंधित अध्ययनों और आंकड़ों का मूल्यांकन किया गया है;

(ग) क्या सरकार नई शिक्षा नीति, 2020 के तहत प्रवेश को युक्तिसंगत बनाने, पाठ्यक्रम और संकाय की गुणवत्ता को उन्नत करने और उद्योग-अकादमिक संबंधों को मजबूत करने के लिए समयबद्ध सुधारों का विचार रखती है; और

(घ) क्या रोजगार योग्यता में सुधार, विद्यार्थियों की परेशानी को कम करने और इंजीनियरिंग शिक्षा को राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाने के लिए लक्षित उपाय लागू किए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): भारत सरकार ने छात्रों के समग्र विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की शुरुआत की। एनईपी का लक्ष्य पूरे देश में शिक्षा की गुणवत्ता में बदलाव लाना और उसे बेहतर बनाना है जिसका उद्देश्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली स्थापित करना है जो समावेशी, न्यायसंगत और उच्च गुणवत्ता वाली हो तथा जो सीखने वालों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए सशक्त बनाए।

छात्रों की रोज़गार-योग्यता को बढ़ाने और एनईपी 2020 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 'राष्ट्रीय क्रेडिट ढांचा' (एनसीआरएफ़) जारी किया गया है जो शैक्षणिक क्षेत्र में कौशल शिक्षा के एकीकरण

को सक्षम बनाता है। यह कौशल संवर्धन पाठ्यक्रमों, मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रमों और क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रमों जैसे विविध क्षेत्रों के साथ-साथ इंटर्नशिप और परियोजनाओं के माध्यम से क्रेडिट संचय को भी सक्षम बनाता है। एनसीआरएफ में कौशल-आधारित पाठ्यक्रमों के माध्यम से आवश्यक कुल क्रेडिट का अधिकतम 50% तक जमा करने का भी प्रावधान है। इन प्रावधानों से उच्चतर शिक्षण संस्थान छात्रों को प्रासंगिक ज्ञान प्रदान करने में सक्षम हुए है जिससे वे उद्योग के लिए तैयार हो सकें।

एनईपी 2020 के उद्देश्यों को प्राप्त करने और तकनीकी शिक्षा के छात्रों को उद्योग-प्रासंगिक ज्ञान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें शामिल हैं:

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा साइंस, अन्तरिक्ष तकनीकी, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग (वीएलएसआई डिज़ाइन और तकनीकी), रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में मॉडल पाठ्यक्रम जारी किए गए हैं। पाठ्यक्रम संशोधन समितियों में उद्योग के हितधारकों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है।
- छात्रों और संकाय सदस्यों की इंटर्नशिप, कौशल विकास और कौशल उन्नयन को सुगम बनाने के लिए, प्रमुख उद्योगों और संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए इंटर्नशिप के मॉडल दिशानिर्देश जारी किए गए। एआईसीटीई द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए जारी किए गए मॉडल पाठ्यक्रम का इंटर्नशिप एक अनिवार्य घटक है। ये दिशानिर्देश पूर्णकालिक या अंशकालिक इंटर्नशिप का प्रावधान करते हैं।
- एआईसीटीई ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 से एआईसीटीई -अनुमोदित संस्थानों में प्रशिक्षुता-युक्त डिग्री/डिप्लोमा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं।
- एआईसीटीई द्वारा 'इंडस्ट्री-एकेडेमिया मोबिलिटी फ्रेमवर्क' शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक अनुप्रयोग के बीच जुड़ाव को सुगम बनाना तथा शिक्षा जगत और उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।
- • नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, पूरे देश में 16,000 से अधिक 'संस्थागत नवाचार परिषदें' (आईआईसी) स्थापित की गई हैं जिनमें 1 लाख से अधिक संकाय सदस्य और 1.5 लाख छात्र नवाचार और उद्यमिता संबंधी गतिविधियों में शामिल हैं।
- वर्ष 2017-18 से, उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के विद्यार्थियों से विचार प्राप्त करने और समस्याओं के लिए अभिनव समाधान तैयार करने हेतु विषय-आधारित वार्षिक हैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। यह विद्यार्थियों में नवाचार, समस्या-समाधान और उद्यमिता की भावना को विकसित करता है।
- संकाय के क्षमता निर्माण के लिए एआईसीटीई ने एआईसीटीई प्रशिक्षण और शिक्षण (अटल) अकादमी के माध्यम से कई प्रशिक्षण कार्यक्रम और संकाय विकास पहलें

शुरू की हैं जिनमें एआई नैतिकता, गहन अधिगम और उद्योग 4.0 में एआई जैसे विषय शामिल हैं।

शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी मद्रास और प्रसिद्ध उद्योग साझेदारों के सहयोग से दिनांक 27 फरवरी 2024 को स्वयम प्लस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। यह प्लेटफॉर्म छात्रों/सीखने वालों को प्रमुख औद्योगिक और अकादमिक विशेषज्ञों की साझेदारी में उच्च-गुणवत्ता वाले अधिगम और प्रमाण पत्र कार्यक्रम उपलब्ध कराता है जिससे उन्हें नए कौशल सीखने, अपने कौशल को बेहतर बनाने और रोज़गार के लिए तैयार होने में मदद मिलती है। इन विषयों में मीडिया, संचार और सूक्ष्म कौशल जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं जिनका उद्देश्य गैर-तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाकर रोज़गार पाने की संभावनाओं को बेहतर बनाना है। शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी मद्रास ने प्रमुख औद्योगिक भागीदारों के साथ 85 से अधिक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। दिनांक1 मार्च 2026 तक की स्थिति के अनुसार इस प्लेटफॉर्म पर 17 विभिन्न क्षेत्रों में 500 से अधिक विषय उपलब्ध हैं और 5.24 लाख से अधिक शिक्षार्थियों ने अपने कौशल विकास के लिए नामांकन कराया है।

शिक्षा मंत्रालय युवाओं को ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण देने और उनकी रोज़गार-योग्यता बढ़ाने के लिए 'राष्ट्रीय प्रशिक्षुतावृत्ति प्रशिक्षण योजना' (एनएटीएस) भी लागू करता है। पिछले 5 वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2024–25) में, एनएटीएस योजना के तहत 12.94 लाख प्रशिक्षुओं को जोड़ा गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, 5 लाख से ज़्यादा प्रशिक्षुओं को जोड़ा गया है।

*****